www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

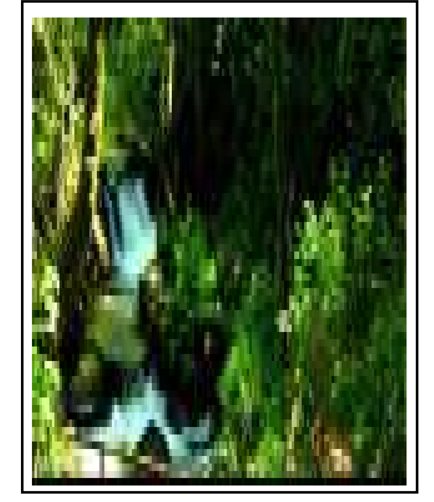

वर्ष – 15 | अंक–34 | RNI-No. : UPHIN/2011/43806 | लखनऊ, शुक्रवार 02 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

नववर्ष में उप्र समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा:सीएम योगी

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नववर्ष के संदेश में नए संकल्प और बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि एक नयी सुबह नयी उम्मीदें लाती है और बदलाव खुद से शुरू होता है।

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को भरोसा जताया कि राज्य 2026 में समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। विपक्षी दलों के नेता मायावती और अखिलेश यादव ने भी नववर्ष के मौके पर शुभकामनाएं दी।आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में 'नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत' की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।''उन्होंने कहा, ''प्रदेश में संचालित विकास एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी रूप से पहुंच रहा है।''मुख्यमंत्री ने कहा, ''पूर्ण विश्वास है कि ईसवी सन्–2026 में डबल इंजन सरकार की विकासपरक नीतियों से उत्तर प्रदेश समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।''बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने देशभर के लोगों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं, और उनके लिए खुशी, शांति, समृद्धि, सुरक्षा और आत्म–सम्मान भरे जीवन की कामना की।मायावती ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''समस्त देशवासियों तथा दुनियाभर में रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनके परिवार वालों को आज नववर्ष सन् 2026 की दिली मुबारकबाद एवं उन सबकी सुख, शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा एवं आत्म–सम्मान व स्वाभिमान–युक्त जीवन की शुभकामनायें।''उन्होंने कहा, ''नया साल देश में सर्वसमाज के हर गरीब व मेहनतकश लोगों अर्थात् समस्त बहुजनों की दिन–प्रतिदिन की जिन्दगी नित्य नये नियम–कानूनों की कदम–कदम पर जकड़नों से दूर सहज व सरल हो तथा यह साल आप सबके लिये बहुत सारी खुशियां लाये, यही कुदरत से कामना ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुजन समाज का थोड़ा अच्छे दिन पाने के लिये यही संघर्ष भी है।''समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नववर्ष के संदेश में नए संकल्प और बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि एक नयी सुबह नयी उम्मीदें लाती है और बदलाव खुद से शुरू होता है।उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''नये साल का नया सवेरा, आशाओं का नया बसेरा, आइए नये रण के लिए नये प्रण लें। नया संकल्प ही नया कल लाता है। हम बदलेंगे तो सब बदलेगा।

मोदी कैबिनेट ने दी 20,668 करोड़ के दो बड़े रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, महाराष्ट्र में सफर होगा 17 घंटे छोटा

नई दिल्ली(एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (ष्टष्टश्व) ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 20,668 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र और ओडिशा में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा।कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे नासिक–सोलापुर–अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। 19,142 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट बीओटी (टोल) मोड पर तैयार किया जाएगा। यह नया कॉरिडोर महाराष्ट्र के नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को कुरनूल से जोड़ेगा। इसके अलावा, इसे वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और नासिक के पास समृद्धि महामार्ग से भी जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक सीधी कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी।

रफ्तार भी और समय की बचत भीइस 6–लेन एक्सेस–कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बनने से यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा समय की बचत का होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर यात्रा की दूरी 201 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर के समय में करीब 17 घंटे की भारी कमी आएगी। वर्तमान में लगने वाले 31 घंटे के समय में लगभग 45त्न की कटौती होगी और गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि इससे लाखों की संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र के अलावा कैबिनेट ने ओडिशा में हृ–326 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को भी मंजूरी दी है।

यह प्रोजेक्ट 1,526.21 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी (श्वक्कष्ट) मोड पर पूरा किया जाएगा। इसके तहत 68.600 किमी से 311.700 किमी तक की मौजूदा 2–लेन सड़क को पक्के शोल्डर वाली सड़क में बदला जाएगा। इस अपग्रेडेशन से दक्षिणी ओडिशा, विशेषकर गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों में संपर्क बेहतर होगा, जिससे स्थानीय बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

देवरिया में शराब की दुकान के पास व्यक्तिपर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शराब की एक दुकान के पास हुए विवाद में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।पुलिस के मुताबिक, घायल व्यक्ति का ईलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जारी है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तरकुलवा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को तरकुलवा बाजार स्थित कंपोजिट शराब की दुकान के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद में संतोष यादव (45) पर चाकू से हमला किया गया।न्होंने बताया कि यादव हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पेट पर चाकू से वार किया गया था। सिंह ने बताया कि मामले दर्ज कर आरोपी अमरजीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

नववर्ष पर डायरी एवं कैलेंडर 2026 का हुआ विमोचन

कार्यक्रम के दौरान सचिव कुमार रवि ने हरित पौधा भेंटकर माननीय मंत्री का स्वागत किया। डायरी और कैलेंडर में निगम द्वारा राज्य में निर्मित विभिन्न भवनों की तस्वीरें एवं जानकारी शामिल की गई है। माननीय मंत्री एवं सचिव ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

पटना (एजेंसी) भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं विभागीय सचिव कुमार रवि के द्वारा नववर्ष के अवसर पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रकाशित डायरी एवं कैलेंडर 2026 का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव कुमार रवि ने हरित पौधा भेंटकर माननीय मंत्री का स्वागत किया। डायरी और कैलेंडर में निगम द्वारा राज्य में निर्मित विभिन्न भवनों की तस्वीरें एवं जानकारी शामिल की गई है। माननीय मंत्री एवं सचिव ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

इस दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से माननीय मंत्री को निगम द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं से अवगत कराया गया। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 2708 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है जिसमें से 2389 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है। 199 परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। निगम द्वारा परियोजना के सुगम अनुश्रवण एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला के निर्माण एवं नियमित अंतराल पर कार्य स्थलों के निरीक्षण की भी जानकारी से अवगत कराया गया।

इसके अलावा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 14 जगहों पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु कार्य किए जा रहे हैं। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 84 संस्थानों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 5 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने कार्य जनवरी, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लाल पहाड़ी, लखीसराय पुरास्थल के पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण तथा विकास कार्य के प्रगति की भी जानकारी दी गई। माननीय मंत्री ने सभी योजनाओं को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने भवनों के रख–रखाव एवं मेंटेनेंस पर जोर देते हुए कहा कि मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड तय करें ताकि भवनों का अच्छे से रख–रखाव हो सके।

नए प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस का भी प्रावधान हो, जिससे कार्य अच्छे से संपादित हो सके। वहीं, सचिव ने निदेशित किया कि प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने भवनों की छतों पर सोलर पैनल के अधिष्ठापन को लेकर भी पदाधिकारियों को निदेश दिया। साथ ही, उन्होंने निगम द्वारा अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की ताकि कार्यों के निष्पादन में कार्य बल की कमी को दूर किया जा सके। इस मौके पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार अनुराग सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

बदरुद्दीन अजमल का असम चुनाव पर बड़ा दांव

35 सीटों पर एआईयूडीएफ की नजर, केरला यूडीएफ से गठबंधन की चर्चा

मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ ने 2026 असम चुनावों के लिए 35 सीटों पर लड़ने और केरल यूडीएफ के साथ गठबंधन की बात कही है, जो कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन का आत्मविश्वास दिखाता है। बिहार चुनावों के नतीजों से प्रेरित अजमल, एआईएमआईएम और यूडीएफ से भी बातचीत जारी रखने की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने 2021 में एआईयूडीएफ से दूरी बना ली थी।

नई दिल्ली (एजेंसी)ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (।प्न्क्थ्) के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 2026 के असम विधानसभा चुनावों के लिए केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं से बातचीत की। AIUDF आगामी विधानसभा चुनावों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं। अजमल ने गुवाहाटी में एक मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को बिहार चुनावों में उसके प्रदर्शन के लिए बधाई दी है।उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी 2026 के असम विधानसभा चुनावों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और दावा किया कि एआईयूडीएफ कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करेगी। अजमल ने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनावों में हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे नतीजे कांग्रेस से बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और बिहार के राजनीतिक नतीजों को देखते हुए उन्होंने आत्मविश्वास जताया। एआईएमआईएम और यूडीएफ के साथ भी बातचीत जारी है। हमने बैठकें और रैलियां शुरू कर दी हैं।2021 के असम विधानसभा चुनावों के बाद, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की कोर कमेटी ने एआईयूडीएफ से संबंध तोड़ने और एआईयूडीएफ को महागठबंधन से बाहर निकालने का संकल्प लिया है। 2021 में कांग्रेस ने दस दलों के नेतृत्व में महागठबंधन बनाया। 12 नवंबर को सात विपक्षी दलों ने 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए असम सोनमिलितो मोर्चा के पुनरुद्धार की घोषणा की।कांग्रेस, असम जातीय परिषद (एजेपी), रायजोर दल, सीपीआई (एम) और तीन अन्य दलों के नेता असम विधानसभा सचिवालय में आयोजित एक बैठक में एकत्रित हुए और एक संयुक्त बैनर तले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया।

चुनाव से पहले कर्मचारियों की बल्ले

बल्ले:तमिलनाडू सरकार ने पोंगल बोनस का किया ऐलान

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आदेशानुसार, तमिलनाडु में सी और डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पोंगल बोनस के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसमें ₹3,000 तक का भुगतान शामिल है। सरकार का लक्ष्य इस पहल से हजारों अस्थायी और संविदा कर्मचारियों सहित लाखों लोगों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने फसल उत्सव पोंगल से पहले कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विशेष पोंगल बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने त्योहारी मौसम के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।सरकारी आदेश के अनुसार, सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल बोनस के रूप में अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, सी और डी श्रेणी के पेंशनभोगियों के साथ–साथ पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये का विशेष भुगतान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय राहत प्रदान करना है, जिनमें से कई लोग घरेलू खर्चों के लिए निश्चित आय पर निर्भर हैं।इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कुल 183.86 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है। इस राशि से सी और डी श्रेणी के पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और पूर्व ग्राम अधिकारियों को पोंगल बोनस का भुगतान किया जाएगा, जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। वित्त विभाग को निर्देश दिया गया है कि धनराशि को बिना किसी देरी के जारी किया जाए ताकि लाभार्थियों को त्योहार से काफी पहले राशि प्राप्त हो सके।नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अलावा, सरकार ने एकमुश्त और समेकित वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिया है। ऐसे कर्मचारियों को पोंगल पैकेज के तहत 1,000 रुपये का विशेष भुगतान मिलेगा। उम्मीद है कि इस कदम से राज्य भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में कार्यरत हजारों अस्थायी और संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी कल्याण और समावेशी विकास पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य परिवारों को त्योहारों से संबंधित खर्चों को वहन करने और पोंगल के मौसम में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करना है। कर्मचारी संघों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि बोनस का समय पर भुगतान बढ़ती महंगाई के बीच बेहद जरूरी राहत प्रदान करेगा।

कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले हिटलर की राह पर, एक दिन इनका अंत होगा:फारूख अब्दुल्ला

नई दिल्ली (एजेंसी)नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले लोग "हिटलर की राह पर चल रहे हैं"। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे "अतिवादी तत्व" समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, यह हमारी नियति है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य कुछ और ही है। वे हिटलर की राह पर चल रहे हैं और हिटलर जैसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं।कश्मीरियों पर हमलों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, लेकिन हिटलर खत्म हो गयाय उसने खुद को गोली मार ली। वहां नाजीवाद का अंत हो गया, यहां भी एक समय आएगा, जब ये अतिवादी तत्व चले जाएंगे।जम्मू–कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने नये साल की शुरुआत पर शांति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, नया साल शुरू हो गया है।

'Safe Drinking Water' का वादा

इंदौर में हाई-लेवल मीटिंग, मंत्री ने माना गंभीर घटना, जल्द होगा सुधार

इंदौर में दूषित पानी से 1400 लोग संक्रमित हुए, हालांकि कोई गंभीर नहीं है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में राहत उपायों पर चर्चा हुई। मंत्री विजयवर्गीय ने निविदाओं के त्वरित समाधान और अधिकारियों की तैनाती का आश्वासन दिया, साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का वादा किया।

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार, इंदौर में दूषित जल की समस्या पर गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई और राहत उपायों का समन्वय किया गया। इस घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 140 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे, शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावत, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, संभागीय आयुक्त सुदाम खाडे, जिला कलेक्टर शिवम वर्मा और इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार उपस्थित थे।बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज हमने बैठक की और निविदा संबंधी मुद्दों (जल आपूर्ति लाइन से संबंधित) और अन्य छोटी–मोटी समस्याओं का समाधान किया, जिनके कारण काम में बाधा आ रही थी। भागीरथपुरा क्षेत्र की निविदा कल तक स्वीकृत हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। शहर में पानी से जुड़ी सभी समस्याओं को पहले हल करने के निर्देश दिए गए हैं। आज यहां दो–तीन अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी क्योंकि अधिकारियों की कमी है और मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ अधिक है। इससे उनका काम कम होगा और उनका कामकाज सुचारू रूप से चलेगा।मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने भागीरथपुरा इलाके का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि मैं अभी भागीरथपुरा से आ रहा हूं और वहां से लगातार मरीज आ रहे हैं। कल से परसों तक 200 लोगों को भर्ती कराया गया। कुल 1400 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 200 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया। किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। आईसीयू वार्ड में इलाज करा रहे लोग भी खतरे से बाहर हैं। हम यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि लोगों को समय पर अच्छा इलाज मिले।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक अस्पताल में, जहां इस बीमारी से प्रभावित मरीजों का इलाज चल रहा है, एक राजस्व अधिकारी और एक स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा, लोगों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह इंदौर के लिए एक बेहद गंभीर घटना है और हम घटना की जड़ तक पहुंचने और इसका समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार, नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।" इसी बीच, मंत्री विजयवर्गीय ने 70 वर्षीय नंदलाल पाल के घर जाकर उनसे मुलाकात की, जिनकी कथित तौर पर दूषित पानी पीने से मृत्यु हो गई थी और परिवार को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ करें अंग्रेजी नव वर्ष 2026 का स्वागत

दीपक कुमार त्यागी

वैसे भी अब देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत नये संकल्प के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से करते हैं। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पिछले वर्ष के दुख–दर्द भूलकर के खट्टी–मीठी यादों से सबक लेकर के अंग्रेजी नव वर्ष को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाएं।

देश व दुनिया में अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के स्वागत की जबरदस्त धूम मची हुई है, इस धूम–धाम को हम लोगों का जोशो–खरोश और चार–चांद लगाने का काम कर रहा है। हम सभी लोग नयी उम्मीद, नयी उमंग, नये विचार, नये संकल्प के साथ अपने–अपने अंदाज व तौर–तरीकों से अंग्रेजी नव वर्ष 2026 का हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि नव वर्ष में शक्तिशाली राष्ट्र के सपने को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार धरातल पर तेजी से काम करेंगी, लेकिन हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए की यह कार्य हम देशवासियों के द्वारा राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता है, हम जिस तरह से अपने हितों के प्रति जुनून के साथ समर्पित रहकर उनकी रक्षा करते हैं, उसी भाव से हमें नियम–कायदे–कानून में रहकर राष्ट्र के प्रति भी समर्पित भाव से रहना होगा, तब ही सशक्त विकसित भारत का निर्माण होगा।

वैसे भी अब देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत नये संकल्प के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से करते हैं। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पिछले वर्ष के दुख–दर्द भूलकर के खट्टी–मीठी यादों से सबक लेकर के अंग्रेजी नव वर्ष को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाएं, हम सभी चाहते हैं कि इस नव वर्ष में हम अपने सभी सपनों को पूरा करें, अपनी व अपनों की झोलियों को खुशियों से भर देने का संकल्प लेकर उसके लिए तय रणनीति के अनुसार जीवन पथ पर कार्य करें। हम चाहते हैं कि बीते हुए समय पर विचार व आत्ममंथन करते हुए, नए लक्ष्य निर्धारित करते हुए, भविष्य में आने वाले जीवन को नयी दिशा देने वाले हर सकारात्मक अवसर को हर हाल में अपनाएं। हम लोग अपनी आकांक्षाओं, संकल्पों के साथ ही नव वर्ष के इस विशेष अवसर को विभिन्न तरीकों से मनाने का कार्य करते हैं। लेकिन उपरोक्त भावों में अगर हम लोग हर वर्ष राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प को भी जोड़ लें तो देशवासियों के जीवन में चार–चांद लग सकते हैं, हम जल्द ही अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सकतें हैं।

वैसे तो नव वर्ष पर दुनिया भर के लोग एक नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही हम लोग बीते हुए कल की कड़वी यादों से सीख लेकर के एक नई शुरुआत भी करने का सकारात्मक प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बीते हुए कल को पीछे छोड़कर के एक नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए सभी आवश्यक आत्म–सुधार के संकल्पों के साथ नव वर्ष का स्वागत करें, हमें यही सिद्धांत राष्ट्रहित की रक्षा के लिए भी लागू करने चाहिए, वैसे भी देखा जाए अंग्रेजी हो या हिन्दू नव वर्ष यह अवसर हम सभी लोगों को सुख–शांति, धन–धान्य, स्वास्थ्य और जीवन पथ पर सफलता की आशाओं के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का कार्य अवश्य करता है। हम लोगों के द्वारा नव वर्ष मनाने का समय व रीति–रिवाज तो अलग–अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके मूल भाव पर गौर करें तो अधिकांश लोगों के लिए यह व्यक्तिगत जीवन में आनंद और व्यक्तिगत विकास के लिए भी नई रणनीति बनाकर के वर्ष भर उस रणनीति पर काम करने की शुरुआत का एक बेहतरीन अवसर होता है, बस हम लोगों को इस रणनीति में अब राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प को और जोड़ना है, जीवन पथ पर लक्ष्यों को तय करते हुए अब वह समय आ गया है कि जब हम राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में आम लोगों की डिक्शनरी व आचरण से राष्ट्रहित सर्वोपरि दूर की बात होता जा रहा है, राष्ट्रहित पर व्यक्तिगत हित बहुत तेजी से हावी होते जा रहे हैं, लोग अपने क्षणिक लाभ के लिए राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा, अमन–चैन, भाईचारे तक को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब वह समय आ गया है कि जब हम राष्ट्रहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ नव वर्ष की शुरुआत करें। आज अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के अवसर पर मैं अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से आप सभी सम्मानित देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं –

ष्नववर्ष में प्रभु श्रीराम की कृपा से पूरी हों सभी आस,

नववर्ष बने खास तेजी से बढ़ें हमारा आत्म–विश्वास, जीवन पथ पर सफल हों हमारा हर अच्छा प्रयास,

जीवन पथ की राहों में ना रहे मुश्किलों का वास,

हल पल परिपूर्ण रहें सकारात्मक ऊर्जा के साथ, हमेशा बना रहें घर व दिल में प्रभु श्रीराम का वास।ष

उपरोक्त चंद पंक्तियों से मैं अंग्रेजी नववर्ष 2026 की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस नव वर्ष में हम सभी लोग राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानेंगे और आपसी वैमनस्य को भूलकर के फिर से एकजुट होकर के अपने जीवन की एक नई पारी की शानदार शुरुआत करते हुए देश निर्माण के लिए दिन–रात एकजुट होकर के कार्य करेंगे और देश का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, वर्ष 2026 में हम देश में एक ऐसा बेहद शानदार सकारात्मक माहौल बनायेंगे, जिसमें हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो और जिसके दम पर भारत विकसित राष्ट्र बनकर जल्द विश्वगुरु बन सकें। इस उम्मीद के साथ ही मैं नव वर्ष के इस पावन बेला पर प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करता हूं कि उम्मीदों के नव वर्ष 2026 में वह प्रत्येक देशवासी की झोली को खुशहाली से भर दें और देश में रामराज्य की अवधारणा को धरातल पर जल्द से जल्द साकार कर दें।

सम्पादकीय

बजट से पहले अर्थव्यवस्था का दुविधाग्रस्त सचः निवेश, कर्ज और मांग का संकट

प्रधानमंत्री के साथ हुई बजट–पूर्व बैठक में अर्थशास्त्रियों द्वारा रखी गई चिंताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा जटिल स्थिति को साफ तौर पर रेखांकित करती हैं। उन्होंने बढ़ती ब्याज एवं मूलधन चुकाने की देनदारी, कमजोर होती घरेलू बचत और सरकार के बढ़े हुए पूंजीगत निवेश के चलते निजी निवेश के समक्ष खड़ी हो रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया। यह संकेत करता है कि आर्थिक वृद्धि के मौजूदा मॉडल की सीमाएं अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगी हैं।

अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि जब सरकार बड़े पैमाने पर पूंजीगत निवेश के लिए बाजार से ऋण लेती है, तो इससे निजी निवेशकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। इस 'क्राउडिंग आउट' प्रभाव के कारण निजी क्षेत्र का निवेश हतोत्साहित होता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ स्थिति नहीं कही जा सकती। इसका सीधा असर यह होता है कि सरकार पर कर्ज और ब्याज चुकाने का बोझ लगातार बढ़ता जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि केंद्रीय बजट का एक चौथाई से भी अधिक हिस्सा केवल ऋण और ब्याज भुगतान में खर्च हो रहा है, जिससे सामाजिक और विकासात्मक व्यय के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। हालांकि, इस तर्क का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि सरकार अर्थशास्त्रियों की सलाह मानकर पूंजीगत निवेश में कटौती करती है, तो मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना फिलहाल अत्यंत कठिन हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ही वह प्रमुख इंजन रहा है, जिसने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है। ऐसे में इसे अचानक कम करना विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने जैसा होगा। निजी निवेश की कमजोरी का कारण केवल महंगा ऋण नहीं है। असल समस्या बाजार में मांग की कमी है। जब निजी क्षेत्र अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता का ही पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा, तो वह नए निवेश का जोखिम क्यों उठाएगा? स्वयं अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि घरेलू बचत गिरकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग सात प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यह गिरावट ऐसे समय में हो रही है, जब विदेशी पूंजी निवेश को लेकर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ी हुई है और चालू खाते का घाटा भी लगभग दो प्रतिशत बना हुआ है, जिसे पाटने के लिए घरेलू संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं। घरेलू बचत में गिरावट का एक सामाजिक–आर्थिक संकेत भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह दर्शाता है कि आम परिवारों का बजट दबाव में है। जब महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ता है, तो बचत स्वाभाविक रूप से घटती है। ऐसी स्थिति में उपभोग में वृद्धि की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और जब उपभोग नहीं बढ़ेगा, तो मांग कमजोर रहेगी, जिससे निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बन ही नहीं पाएगा। इन तमाम कारकों को देखें, तो स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार के दुश्चक्र में फंस गई हैकृकम मांग, कमजोर निजी निवेश, बढ़ता सरकारी कर्ज और घटती घरेलू बचत। इस बीच सरकार के लिए पूंजीगत निवेश घटाना एक जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है, लेकिन कर्ज और राजकोषीय घाटे को अनियंत्रित छोड़ देना भी दीर्घकाल में खतरनाक है। सामान्य परिस्थितियों में ऋण और राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन बनाने की सलाह पूरी तरह उचित मानी जाती। किंतु सवाल यह है कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में इस सिद्धांत पर कठोरता से अमल करना व्यावहारिक होगा? शायद जरूरत इस बात की है कि बजट में ऐसे उपाय किए जाएं, जो एक ओर मांग को प्रोत्साहित करें, आम परिवारों की आय और बचत क्षमता बढ़ाएं, और दूसरी ओर निजी निवेश के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार करें। सरकार ने अर्थशास्त्रियों की इन चेतावनियों और सुझावों से क्या ग्रहण किया है, इसका वास्तविक संकेत आगामी बजट में ही मिलेगा। बजट न केवल वित्तीय दस्तावेज होगा, बल्कि यह भी बताएगा कि सरकार इस जटिल आर्थिक दुविधा से निकलने के लिए कौन–सा रास्ता चुनती है।

वोट बैंक का लालच बना है पर्यावरण विनाश का कारण

योगेंद्र योगी

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड देश का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा भारी तबाही मचाती है। जिससे जानकृमाल का भारी नुकसान होता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। इसमें विकास के नाम पर वनों का विनाश और वन भूमि पर अतिक्रमण प्रमुख है।

वोट बैंक का लालच सत्तारुढ़ दलों को इस कदर हाथ बांधे रखने के लिए मजबूर रखता है कि बेशक प्राकृतिक आपदाओं के विनाश से लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इसकी सरकारों को चिंताकृपरवाह नहीं है। लगता है उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है हर हाल में वोट बैंक को बनाए रखना। ऐसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति तब सामने आई सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूकदर्शक की तरह बैठे रहे और अदालत ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड देश का सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। हर साल होने वाली प्राकृतिक आपदा भारी तबाही मचाती है। जिससे जानकृमाल का भारी नुकसान होता है। इसका प्रमुख कारण है प्रकृति से छेड़छाड़। इसमें विकास के नाम पर वनों का विनाश और वन भूमि पर अतिक्रमण प्रमुख है। पिछले आठ वर्षों में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 3,554 लोगों की जान गई, 5,948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। मानसून का मौसम लगातार घातक साबित होता है, जिससे राज्य की पहले से ही नाजुक भूभाग पर हर साल एक नया घाव हो जाता है। बादल फटने से धारली में आई भीषण बाढ़ में 5,948 लोग घायल हुए और अरबों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।उत्तराखंड एक खतरनाक चक्र में फंस गया है। व्यापक और सक्रिय आपदा प्रबंधन के अभाव में, ष्देवभूमिष (देवताओं की भूमि) प्रकृति के प्रकोप से लगातार क्षतिग्रस्त होती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दशकों से हो रही देवदार के पेड़ों की कटाई ही उत्तरकाशी में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण है। देवदार के पेड़ों की जड़ें घनी होती हैं जो मिट्टी को बांधकर रखती हैं, कटाव को रोकती हैं और भारी बारिश या भूस्खलन के दौरान मलबे और पानी के बहाव को रोककर संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि यदि धराली में ऐतिहासिक देवदार के वन क्षेत्र बरकरार रहते, तो इस आपदा का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता, या शायद नगण्य ही हो जाता।एक समय उत्तराखंड के ऊंचे और हिमालयी क्षेत्र दृ विशेष रूप से समुद्र तल से 2,000 मीटर से ऊपर के इलाके दृ देवदार के घने जंगलों से आच्छादित थे। प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 400 से 500 देवदार के पेड़ पाए जाते थे। वन, जो प्राकृतिक ढलानों को स्थिर रखते हैं, उनकी कमी से जल निकासी बाधित होती है और पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है, जिससे आपदाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पेड़–पौधे मिट्टी को जकड़कर रखते हैं। जब पेड़ कटते हैं, तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भारी बारिश के दौरान आसानी से बह जाती है, जिससे भूस्खलन और मलबा प्रवाह होता है, जैसा कि 2013 के केदारनाथ आपदा में देखा गया था।5 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई विनाशकारी आपदा ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हिमालयी राज्य की दीर्घकालिक संवेदनशीलता को उजागर कर दिया था। इस त्रासदी में 66 लोग लापता हुए। पिछले एक दशक में राज्य में लगभग 18,464 प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गई, जिनसे भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास कई बड़ी आपदाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1991 के उत्तरकाशी भूकंप में 768 लोगों की जान गई, उसके बाद 1998 के मालपा भूस्खलन (225 मौतें) और 1999 के चमोली भूकंप (100 मौतें) का नंबर आता है। साल 2013 की केदारनाथ बाढ़ सबसे विनाशकारी रही, जिसमें 5,700 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि 2021 की रेनी आपदा में मरने वालों की संख्या में 206 रही। पिछले एक दशक में दर्ज की गई 18,464 घटनाओं में से चौंका देने वाली 12,758 घटनाएं भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण हुईं।भारत में 2024–2025 के आंकड़ों के अनुसार, 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण है, जो कि दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है।

मध्य प्रदेश और असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहाँ लाखों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी बड़ी मात्रा में वन भूमि अतिक्रमित है। जिससे वन, वन्यजीव और पर्यावरण को गंभीर खतरा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा देश भर में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक वन भूमि पर सर्वाधिक अतिक्रमण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश और असम सबसे आगे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्य भी महत्वपूर्ण अतिक्रमण वाले राज्यों की सूची में शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया था कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13,056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत था। इनमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर और दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने वन अतिक्रमण से संबंधित आंकड़े और विवरण प्रस्तुत नहीं किए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की सरकारें पर्यावरण और वनों के विनाश को रोकने के लिए कितनी चिंतित हैं। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं है। कारण साफ है इससे वोट नहीं मिलते, उल्टे वन भूमि पर अतिक्रमियों को हटाने से वोट बैंक का नुकसान होता है। यही वजह है कि सभी दल ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं।

जब्ती करों से लोक-केंद्रित सुधार तकः 2025 में भारत की कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव

1930 में, महात्मा गांधी द्वारा नमक कर की अवज्ञा ने उजागर किया था कि कैसे दमनकारी कर प्रणाली नागरिक को राज्य से दूर कर सकती है। यह एक चेतावनी थी कि जब कर मनमाने या अत्यधिक होते हैं, तो वे विश्वास और सामाजिक सम्ध्पर्क को कमजोर करते हैं। चार दशक बाद, भारत में एक और चरम स्थिति देखी गई, जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आयकर के स्तर को आश्चर्यजनक रूप से 97.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इस परम्ध्परा ने करदाताओं और राज्य के बीच गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। दशकों तक, भय के कारण अनुपालन होता रहा। इसने सक्रिय योगदान देने के बजाय टालमटोल को प्रोत्साहित किया। इसी पृष्ठभूमि में मोदी सरकार के कर सुधार, जो 8 वर्ष पहले आरंभ हुए और 2025 में निर्णायक रूप से आगे बढ़े, अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक हैं। इस बदलाव में अंतर्निहित लाफर कर्व का तर्क यह है कि कम कर दरें राजस्व सृजन के लिए उप–इष्टतम हैं और कर आधार का विस्तार करती हैं। इस प्रकार भारत के 2025 के कर सुधार न केवल राजकोषीय परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि एक दार्शनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उत्ध्पीड़न से सहयोग तक और अविश्वास से लेकर राज्य और नागरिक के बीच एक नया सामाजिक अनुबंध है। जीएसटी से पहले की वास्तविकतारू विखंडन, रिसाव और अविश्वास वैट शासन के दौरान, अप्रत्यक्ष करों की बहुलता ने व्यापक स्ध्तर पर भ्रम पैदा किया , राज्यों ने 0 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के एकसमान स्लैब को खत्ध्म करते हुए बार–बार वैट दरों में बदलाव किया।

वास्तव में, स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, राज्यों ने अतिरिक्त शुल्क लगाने के विरूद्ध अपनी 2010 की रिपोर्ट में कैग की सुस्ध्पष्ध्ट सलाह की अनदेखी कर दी, फिर भी प्रवेश कर और स्थानीय अधिभार जारी रहे। इसने भ्रम और विखंडन पैदा किया और प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के अनुपालन नियमों, दंड और प्रक्रियाओं को लागू किया।

इसके गंभीर परिणाम हुए। कमजोर जांच और असंगत प्रवर्तन ने कर चोरी को प्रोत्साहित किया। हर दो डीलरों में से एक ने कर चोरी करने का प्रयास किया और सिर्फ एक मामले में ही, सात डीलरों को उचित दस्तावेज के बिना 1,026 करोड़ रुपये की छूट दे दी गई। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (2025)रू कार्यनीति के रूप में सरलता

वर्ष 2017 में जीएसटी की शुरुआत ऐतिहासिक थी। इसने भारत को एकल बाजार में समेकित किया, व्यापक करों को समाप्त कर दिया और एक पारदर्शी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की नींव रखी। यद्िप, दरों और वर्गीकरण में अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हुए और निस्संदेह

अनुपालन के साथ–साथ पंजीकरण में भी भारी समस्याएं रहीं।

उदाहरण के लिए, वस्ध्त्र क्षेत्र में धुलाई और रंगाई जैसी सेवाओं पर ष्जॉब वर्क सर्विसेजष के हिस्से के रूप में 5 प्रतिशत कर लगाया गया था, जबकि ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और रासायनिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाया गया था। इससे वर्गीकरण को लेकर गंभीर भ्रम और कर विवाद पैदा हो गए। इन चुनौतियों को स्ध्वीकार करते हुए मोदी सरकार ने 2025 में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत की, जो जीएसटी के लॉन्च के बाद से सबसे सार्थक सरलीकरण प्रदान करते हैं। इस प्रणाली को दो स्पष्ट स्लैब, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में युक्तिसंगत बनाया गया था। साथ ही, वस्तुओं के वर्गीकरण को भी स्पष्ट किया गया, अनुपालन को सरल बनाया गया और पंजीकरण को सुगम बनाया गया।

पिछले 8 वर्षों में सरकार ने सक्रिय रूप से व्यवसायों और राज्यों की बात सुनी है और राज्यों को कार्यान्वयन में समान भागीदार माना है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया कि सुधारों को सुचारू रूप से लागू किया जाए।

2025 के जीएसटी सुधारों ने करों को सरल बनाने से कहीं अधिक काम कियाय उन्होंने कई सेक्ध्टरों में मांग को सीधे तौर पर प्रेरित किया।

भारत में दीपावली के अवसर पर 6.05 ट्रिलियन रूपये की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक है। एक दशक से अधिक समय में यह इसकी सबसे मजबूत नवरात्रि बिक्री रही है। साथ ही, अक्टूबर 2025 में ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री 40.5 प्रतिशत बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

जिन आलोचकों ने यह तर्क दिया था कि जीएसटी को सरल बनाने और दरों को तर्कसंगत बनाने से कर राजस्व में कमी आएगी, वे भी गलत साबित हुए। अक्टूबर–नवंबर 2025 में, जीएसटी में महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद, सकल जीएसटी संग्रह 2024 में इसी अवधि की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक था। जीएसटी दरों में कटौती और आयकर छूट की सीमा में वृद्धि से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिलेगी। सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 0 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो 18 प्रतिशत से कम है। इसका अर्थ है कि 20,000 रुपये के बेस प्रीमियम पर पहले 3,600 रुपये जीएसटी (18 प्रतिशत) था, जिससे 23,600 रुपये देय था। छूट के बाद, 20,000 रुपये के भुगतान पर सीधे 3,600 रुपये की बचत है। जीएसटी में सुधार से किराने का सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के घरेलू बिलों में 13 प्रतिशत की बचत होगी, जबकि एक छोटी कार का खरीदार लगभग 70,000 रुपये बचा सकता है। एसी खरीद में 2,800 रुपये की बचत होगी क्योंकि इन वस्तुओं की जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाकर और आवश्यक एवं आकांक्षी दोनों वस्तुओं पर कर के बोझ को कम करके, सरकार ने आत्मविश्वास से व्ध्यय करने और निरंतर मांग का वातावरण सृजित किया। मध्यम वर्ग के लिए कर में महत्ध्वपूर्ण लाभ

भारत की आयकर यात्रा इसके आर्थिक विकास को दर्शाती है। इंदिरा गांधी के युग में कर की दर 97.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और कर चोरी और अविश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। दशकों बाद, उदारीकरण के बावजूद, 2014 में राहत मामूली रहीय आयकर छूट को 2 लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया था, जो शहरीकरण की अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं था।

मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कर के बोझ को निरंतर कम किया है, प्रासंगिक उपायों पर नीतिगत स्थिरता को प्राथमिकता दी है। पिछले दशक में आयकर छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपये से बढ़कर 2025 में 12 लाख रुपये हो गई है, जो 6 गुना राहत प्रदान करती है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, 75,000 रुपये की मानक कटौती के बाद, प्रभावी शून्य–कर सीमा अब 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष है। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा जबकि 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को टैक्स के रूप में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। नमक कर से लेकर आयकर की जब्ती दरों तक, भारत का इतिहास बताता है कि त्रुटिपूर्ण कर प्रणाली विश्वास और विकास को कमजोर करती है। मोदी सरकार के 2025 के कर सुधार उस अतीत से एक स्पष्ट अंतर का प्रतीक है। सरलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर, राज्य ने उपभोग में वृद्धि करते हुए अनुपालन को सुदृढ़ किया है। 2025 में, भारत में कर प्रणाली अब नियंत्रण का माध्ध्यम नहीं रह गई है। यह एक साझेदारी है, जो यह मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है।

नव वर्ष 2026: चुनौतियों के बीच संकल्प, एकजुटता और आत्मबल की परीक्षा

नव वर्ष के आरंभ पर यह कामना स्वाभाविक है कि 2026 भारत के लिए खुशहाली, स्थिरता और अमन–चैन का वर्ष सिद्ध हो। किंतु कामनाओं से आगे बढ़कर यदि इस दिशा में ठोस संकल्प और व्यावहारिक प्रयास किए जाएं, तो यह लक्ष्य असंभव नहीं है। कम–से–कम इतना तो अवश्य सुनिश्चित किया ही जा सकता है कि जब यह वर्ष विदा ले, तब देश आज की तुलना में अधिक सुरक्षित, सशक्त और संतुलित स्थिति में हो। हालांकि, इस दिशा में पहला और सबसे कठिन कदम हैकृ मौजूद चुनौतियों के साथ–साथ अपनी आंतरिक कमजोरियों को स्वीकार करना। नए साल का आगमन ऐसे समय हुआ है, जब आर्थिक दबाव, सुरक्षा संबंधी खतरे और भू–राजनीतिक अनिश्चितताएं एक साथ गंभीर रूप ले चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर जारी उथल–पुथल का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गुजरा वर्ष यह चेतावनी देकर गया है कि सीमापार प्रायोजित आतंकवाद के साथ–साथ देश के भीतर भी कट्टरपंथी और हिंसक प्रवृत्तियां सक्रिय हैं, जो अवसर की तलाश में रहती हैं। पड़ोसी देशों की हालिया घटनाओं ने इन आशंकाओं को और बल दिया है। विशेष रूप से बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव ने उस सीमा पर भी सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता पैदा कर दी है, जिसे कुछ समय पहले तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जा रहा था। पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर चुनौतियां कम होने के बजाय और जटिल हुई हैं, जबकि चीन के साथ संबंधों में भले ही संवाद की बहाली हुई हो, लेकिन विश्वास की जमीन अब भी भुरभुरी बनी हुई है। इन सबके ऊपर वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव यह संकेत देते हैं कि संकट की घड़ी में भारत को बाहरी सहायता पर निर्भर रहने की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। अमेरिका सहित किसी भी बड़े देश से बिना शर्त समर्थन की अपेक्षा करना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है। ऐसे में भारत के लिए आंतरिक शक्ति, सामाजिक एकता और संस्थागत मजबूती ही सबसे बड़ा संबल बन सकती है। दुर्भाग्य से, देश के भीतर बढ़ता अविश्वास, सामुदायिक विभाजन, क्षेत्रीय तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों को कमजोर कर रहे हैं। इन कारणों से संपूर्ण एकजुटता और दृढ़ संकल्प हासिल करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है।

अतः नव वर्ष का सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि हम इन आंतरिक दरारों को पाटने और राष्ट्रीय एकता को पुनः केंद्र में लाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसके लिए पहल की स्वाभाविक जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व पर ही आती है। सत्ता और विपक्षकृदोनों को संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर देशहित में संवाद, सहयोग और संयम का परिचय देना होगा।

साथ ही, नागरिक समाज, मीडिया और संस्थानों की भी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। आलोचना आवश्यक है, लेकिन वह रचनात्मक होय असहमति हो, पर वह विभाजनकारी न बने। नव वर्ष 2026 तभी वास्तव में शुभ सिद्ध होगा, जब भारत चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार कर, आत्मबल और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता चुने।

अब प्रश्न यही हैकृक्या राजनीतिक नेतृत्व और समाज, दोनों मिलकर इस संकल्प को व्यवहार में उतार पाएंगे? आने वाला वर्ष इसी प्रश्न का उत्तर देगा।

नववर्ष पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय में उमड़ा जनसैलाब, अखिलेश यादव ने 2027 में भाजपा सरकार हटाने का किया आह्वान

लखनऊ (संवाददाता)।नववर्ष के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, पत्रकारों, समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदेश मुख्यालय 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ पहुंचकर मुलाकात की और नववर्ष की बधाई दी। अखिलेश यादव ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।इस अवसर पर अखिलेश यादव ने सभी को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में यह संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर देश और समाज को खुशहाली की दिशा में आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में सभी को नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ मिलकर काम करना है।पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में भाजपा की नकारात्मक सरकार को सत्ता से हटाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा सरकार का जाना तय है।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कमजोर हो चुकी है और जब भाजपा कमजोर होती है तो वह और अधिक साम्प्रदायिक हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, साइबर क्राइम और फ्राड लगातार बढ़ रहा है तथा डायल 100 और 1090 जैसी सेवाओं को खराब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है और भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है, जिसके संरक्षण में जिलों–जिलों में गरीबों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने अरावली पहाड़ों को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है और गंगा, गोमती, यमुना सहित सभी नदियों को बर्बाद कर दिया गया है। नदियों की सफाई के लिए आया बजट लूट लिया गया। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और खाद की कालाबाजारी हो रही है।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पीडीए को आरक्षण नहीं देना चाहती और नौकरियों की लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पीडीए की हजारों नौकरियां छीनी हैं और पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए एक वैकल्पिक सामाजिक ताकत है और जो पीडीए के खिलाफ है, वह संविधान, अधिकार और सम्मान के खिलाफ है।उन्होंने भाजपा को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि यह हर वर्ग को धोखा देती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सब मिलजुलकर रहते हैं और सबका सम्मान होता है। जनता को भाजपा सरकार ने परेशानी और संकट में डाल दिया है, इसलिए जनता के हित में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026, वर्ष 2027 की ओर ले जा रहा है और विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में जुट जाना चाहिए और जनता के सुख–दुख के साथी बनना चाहिए।अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का रास्ता संविधान का रास्ता है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये दिए जाएंगे और पार्टी जो वादा करती है उसे निभाती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में किसान, मजदूर और गरीब सभी का भला होगा, फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विकास कार्य ठप हैं और बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हो रही है। लोगों को बिजली कम मिलती है और बिल अधिक आता है, जबकि सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी नया बिजली कारखाना नहीं लगाया।नववर्ष के अवसर पर रायबरेली के शिवा विश्वकर्मा ने अखिलेश यादव को संगीत बजने वाला छोटा ट्रैक्टर भेंट किया, वहीं लक्ष्मण निषाद ने सिंघाड़ा भेंट किया।

नववर्ष 2026 पर बहन कु. मायावती का बड़ा संदेश, बहुजनों की जिंदगी सहज-सरल बने और विकास का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुचे

लखनऊ, (संवाददाता)बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं और पूर्व सांसद बहन कु. मायावती ने नववर्ष सन् 2026 के अवसर पर समस्त देशवासियों तथा दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और उनके परिवारजनों को दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने सभी के सुख, शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा तथा आत्म–सम्मान और स्वाभिमान से युक्त सौहार्दपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं दी हैं।बहन कु. मायावती ने कहा कि नया साल देश में सर्वसमाज के गरीबों और मेहनतकश लोगों, अर्थात् समस्त बहुजनों की दिन–प्रतिदिन की जिंदगी को नित्य नए नियम–कानूनों की कदम–कदम पर होने वाली जंजाल और जकड़न से मुक्त करते हुए सहज और सरल बनाए। उन्होंने कहा कि यह वर्ष सभी के लिए खुशियां लेकर आए, यही कुदरत से कामना है और यही राजनीतिक व सामाजिक जीवन में बहुजन समाज के लिए अपने थोड़े अच्छे दिनों की दिशा में जारी संघर्ष का भी उद्देश्य है।उन्होंने कहा कि विशाल जनसंख्या वाले भारत और आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज आज भी अपार गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त जीवन जी रहा है। ऐसे में बहुप्रचारित विकास का लाभ कल्याणकारी संविधान की भावना के अनुसार केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित न रहकर सभी अति–जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचे, तभी वास्तविक और न्यायपूर्ण विकास संभव होगा। इसके लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रति व्यक्ति विकास दर को मजबूती प्रदान कर उसे बेहतर बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि आमजन के भी थोड़े अच्छे दिन आ सकें।बहन कु. मायावती ने कहा कि संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप कानून के राज की स्थापना हर स्तर पर जरूरी है। इसके लिए हर प्रकार के द्वेष, घृणा और नफरती हिंसा से समाज को मुक्त कराने के उद्देश्य से आपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि नए साल में लोग वास्तविक बदलाव को महसूस कर सकें और देशभर में खासकर घृणा व नफरती तनाव और हिंसा का जो माहौल बनाने का षड्यंत्र जारी है, उसका देश और जनहित में अंत हो।उन्होंने कहा कि इसके लिए खासकर सत्ताधारी दल तथा केंद्र और राज्य सरकारों को भारत की विशिष्ट संवैधानिक पहचान 'अनेकता में एकता' और 'सर्व धर्म समभाव' के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना होगा। सभी धर्मों को समान सम्मान तथा प्रत्येक नागरिक के जान–माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित किए बिना देश में बहुप्रतीक्षित समतामूलक विकास संभव नहीं है। विकास ऐसा होना चाहिए जो अमीरी–गरीबी की खाई को और बढ़ाने वाला न होकर समाज के हर वर्ग की तरक्की सुनिश्चित करे।बहन कु. मायावती ने कहा कि यदि देश इन संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर चलेगा, तभी वह विश्व स्तर पर पथ–प्रदर्शक बन सकेगा, जिसका लाभ देश–दुनिया में रहने वाले सभी भारतीयों को मिलेगा और पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध बेहतर होकर आमजन के जीवन को और बेहतर बनाएंगे।केंद्र सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को हीन या बोझ समझने के बजाय मानव संपदा मानकर उन पर निवेश करने की नीति बनाई जानी चाहिए। इससे देश की वास्तविक संपत्ति का विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि केवल बड़े उद्योगपतियों और धन्नासेठों की तिजोरियां भरने से अरबपतियों और खरबपतियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन गरीब बहुजन समाज का जीवन आज भी मुट्ठी भर सरकारी अन्न और सहायता का मोहताज बनकर लाचार और मजबूर बना हुआ है।बहन कु. मायावती ने कहा कि नए साल में देश और जनहित से जुड़े इन अति–जरूरी मुद्दों पर यदि सही नीयत और नीति के साथ ईमानदार प्रयास किए जाएं तो यही नववर्ष का सच्चा संदेश होगा। साथ ही यह भी जरूरी है कि चुनाव जनमत से अधिक जुगाड़ का तंत्र बनकर न रह जाएं, क्योंकि यही लोकतंत्र और देशहित में उचित है।

बिजली बिल राहत योजना:2025 के प्रथम चरण की अवधि तीन दिन बढ़ी, 03 जनवरी तक मिलेगा लाभ

लखनऊ (संवाददाता)।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की संवेदनशील और जनहितकारी पहल पर बिजली बिल राहत योजनादृ2025 के प्रथम चरण की अवधि को तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। पहले चरण के अंतिम दिन देर रात तक चले राहत शिविरों में उमड़ी भारी भीड़, आमजन की व्यापक भागीदारी और योजना के प्रति दिखाई गई गहरी रुचि को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब यह योजना, जो पहले दिसंबर माह तक सीमित थी, 03 जनवरी तक लागू रहेगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र विद्युत उपभोक्ता इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे।बिजली बिल राहत योजनादृ2025 का प्रथम चरण ऐतिहासिक रूप से अत्यंत सफल रहा है। ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा के कुशल नेतृत्व और सतत निगरानी में प्रदेशभर में आयोजित राहत शिविरों के माध्यम से लगभग 31 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाया। इस दौरान उपभोक्ताओं को 5363 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली बिल छूट प्रदान की गई, जो प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।इस योजना के अंतर्गत वर्षों ही नहीं बल्कि दशकों पुराने बकाया बिजली बिलों पर भी उपभोक्ताओं को तीन–चौथाई तक की छूट दी गई है। इससे लाखों परिवारों को लंबे समय से चले आ रहे सरकारी बकाये के मानसिक और आर्थिक बोझ से राहत मिली है। विशेष रूप से गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना राहत की बड़ी सौगात बनकर सामने आई है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।बिजली बिल राहत योजना ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की जनहितकारी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसमें शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। उनका मानना है कि सरकार का दायित्व केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिक को राहत देकर उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसी भावना के तहत योजना की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।ऊर्जा मंत्री ने सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 03 जनवरी तक अपने नजदीकी बिजली बिल राहत शिविरों में पहुंचकर योजना का लाभ अवश्य उठाएं और वर्षों से चले आ रहे बकाया बिजली बिलों के बोझ से स्वयं को मुक्त करें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक राहत का एक मजबूत आधार बनेगी तथा आमजन के जीवन में स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में गायत्री देवी के सेवानिवृत्ति अवसर पर भावभीना विदाई समारोह

लखनऊ (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब में विगत 31 दिसंबर 2025 को संस्थान की वरिष्ठ आशु लिपिक एवं पूर्व वैयक्तिक सहायक महानिदेशक, गायत्री देवी के शासकीय सेवा की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के अवसर पर गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन महानिदेशक संस्थान एल. वेंकटेश्वर लू के मार्गदर्शन तथा प्रभारी अपर निदेशक सुबोध दीक्षित की अध्यक्षता एवं प्रशासनिक नियंत्रण में संपन्न हुआ।विदाई समारोह के दौरान संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गायत्री देवी को पुष्प गुच्छ एवं उपयोगी उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके दीर्घ शासकीय सेवा काल को स्मरण करते हुए उनकी सरलता, सहज व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठा, लगन और ईमानदारी की सराहना की तथा संस्थान के प्रति उनके योगदान को प्रेरणास्पद बताया।समारोह के समापन अवसर पर प्रभारी अपर निदेशक सुबोध दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि शासकीय सेवा के अनुभवों के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें व्यक्ति को परिवार और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने अनुभवों का सकारात्मक उपयोग करने का अवसर मिलता है। उन्होंने गायत्री देवी के उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की।कार्यक्रम का संचालन सहायक निदेशक राजीव कुमार दूबे ने किया। आयोजन को सफल बनाने में संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही।

इटौंजा थाना क्षेत्र में किशोर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, वैधानिक कार्रवाई जारी

लखनऊ (संवाददाता)। थाना इटौंजा क्षेत्र के ग्राम किशुनपुर, पोस्ट उसरना में एक किशोर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। दिनांक 01 जनवरी 2026 को समय लगभग 06रू40 बजे ग्राम निवासी रामगोपाल पुत्र स्व. गिरधारी ने थाना इटौंजा पर सूचना दी कि उनके पुत्र सचिन (उम्र लगभग 14 वर्ष) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।सूचना प्राप्त होते ही उपनिरीक्षक अंकुर कुमार द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किशोर सचिन ने अपने घर के कमरे की छत में लगे पंखे के कुंडे से प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक किशोर को पूर्व से मिर्गी (दौरे) की बीमारी थी।घटना के संबंध में शव का पंचायतनामा भरने सहित अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में नववर्ष 2026 पर कार्यक्रम, कुलपति ने विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में योगदान का आह्वान किया

लखनऊ (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दिनांक 1 जनवरी को नववर्ष 2026 के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रो. नरेंद्र कुमार, प्रॉक्टर प्रो. राम चंद्रा तथा गृह विज्ञान विद्यापीठ की संकायाध्यक्ष प्रो. यूवी किरण विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत बाबासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि समाज की समस्याओं को समझना और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनके समाधान के लिए सतत प्रयास करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वयं को ज्ञान, क्षमता और कौशल के स्तर पर सक्षम बनाते हैं, तो समाज के लिए अधिक सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। कुलपति ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों की यह विशेष जिम्मेदारी है कि यहां होने वाला शोध, शिक्षण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां समाजोपयोगी हों।उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमताओं का निरंतर विकास करते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि विकसित भारतदृ2047 के संकल्प को साकार करने में विश्वविद्यालय अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2026 भारत को एक नए प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला सिद्ध होगा, यदि सभी मिलकर सकारात्मक सोच और कर्मठता के साथ आगे बढ़ें।कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के सफाई सेवकों और मालियों को शॉल एवं मिष्ठान भेंट कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्वविद्यालय परिसर की स्वच्छता, सौंदर्य और सुव्यवस्था बनाए रखने में उनके द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ और सराहनीय योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया। इस सम्मान से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हुई और उनके भीतर कार्य के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ।नववर्ष के अवसर पर आपसी सौहार्द और सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी के लिए तेहरी भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने सहभागिता की और उत्साहपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम का आनंद लिया।सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, अधिकारीगण, गैर–शिक्षण कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

महिगवां थाना क्षेत्र में दुष्कर्म व पाक्सो के गंभीर मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल फोन बरामद

लखनऊ (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के जोन उत्तरी अंतर्गत थाना महिगवां पुलिस ने दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत से जुड़े गंभीर मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई 01 जनवरी 2026 को जारी प्रेस नोट के तहत की गई।पुलिस के अनुसार दिनांक 02 दिसंबर 2025 को वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना महिगवां में मु0अ0सं0 151ध2025 के अंतर्गत बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा 5एमध6 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आरोप है कि अभियुक्त ने वादिनी को कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी, मोबाइल फोन तोड़ दिया तथा वादिनी की लगभग दो से ढाई वर्ष की पुत्री के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसकी गलत वीडियो भी बनाई। इस अत्यंत संवेदनशील मामले की विवेचना अति निरीक्षक मथुरा राय द्वारा की जा रही थी।दिनांक 31 दिसंबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम चौकी पहाड़पुर क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त परसऊ मोड़ के पास खड़ा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल की मदद से उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान रंजीत पुत्र मोलहेराम निवासी ग्राम सरसवां, थाना महिगवां, उम्र करीब 39 वर्ष के रूप में हुई, जो प्लाटिंग का कार्य करता है।पुलिस ने अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 31 दिसंबर 2025 को समय लगभग 19रू07 बजे हिरासत में लिया।

जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसे सील कर विधिवत मालखाने में जमा कराया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी की पूरी प्रक्रिया के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया गया।पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पहले से मौजूद है। उसके विरुद्ध वर्ष 2023 में थाना बीकेटी में मारपीट व धमकी तथा वर्ष 2024 में थाना महिगवां में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अन्य थानों और जनपदों से भी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्र की जा रही है।पुलिस का कहना है कि विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को दिनांक 01 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्रवाई को महिला और बाल सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताते हुए पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी के मंदिरों में नए साल को लेकर विशेष तैयारी,तड़के से खुल जाएगा कपाट

लखनऊ, (संवाददाता)। न्यू ईयर 2026 के स्वागत को लेकर राजधानी लखनऊ के मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां एक ओर लोग जश्न और पार्टी की प्लानिंग में जुटे हैं, वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल की पहली सुबह भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। 1 जनवरी को मंदिरों में दर्शन करना आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसी को देखते हुए लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा–अर्चना, दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर समितियों का कहना है कि 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन और स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। न्यू ईयर 2026 के मौके पर हनुमान सेतु मंदिर, श्री श्याम मंदिर, हनुमत धाम मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, चौक स्थित बड़ी काली मंदिर और अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। इन मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए कतार प्रणाली, सुरक्षा जांच और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री श्याम मंदिर समिति के पदाधिकारी पंकज मिश्रा ने बताया कि नववर्ष पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है।

मलिहाबाद के कस्मडीखुर्द गांव में मिशन शक्ति अभियान, ग्राम चौपाल के जरिए महिला सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता

लखनऊ (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अंतर्गत थाना मलिहाबाद द्वारा मिशन शक्ति फेज–5.0 के तहत ग्राम कस्मडीखुर्द में महिला सुरक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम 01 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम चौपाल के माध्यम से पुलिस–जनता संवाद स्थापित कर महिलाओं और बालिकाओं के बीच सुरक्षा के प्रति विश्वास को मजबूत किया गया।पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद के सभी 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों पर निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है, ताकि थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।इसी क्रम में थाना मलिहाबाद की टीम द्वारा ग्राम कस्मडीखुर्द में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव की लगभग 25 से 30 महिलाएं, बालिकाएं और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को थाना स्तर पर स्थापित महिला सुरक्षा केंद्र और मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी दी गई, साथ ही महिला संबंधी सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।पुलिस टीम ने महिलाओं को आपात स्थिति में सहायता के लिए 112, 1090, 181, 1076, 101 और 108 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजिटल अरेस्ट जैसी भ्रांतियों को दूर किया गया और ओटीपी साझा न करने, अनजान लिंक से बचने तथा ऑनलाइन भुगतान में सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई।

नगर निगम लखनऊ का संपूर्ण समाधान दिवस आज, महापौर की अध्यक्षता में शहरवासियों की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण

लखनऊ (संवाददाता)। शहरवासियों की शहरी समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है। यह कार्यक्रम नगर निगम मुख्यालय, लालबाग स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। समाधान दिवस की अध्यक्षता महापौर सुषमा खर्कवाल करेंगी।संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इनमें गृहकर और जलकर से संबंधित विवाद, सफाई व्यवस्था, सड़कों और गलियों की मरम्मत, सीवर लाइन व ड्रेनेज से जुड़ी दिक्कतें, स्ट्रीट लाइट की खराबी, कूड़ा उठान सहित अन्य नगर निगम से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। इसके साथ ही जीआईएस सर्वेक्षण के उपरांत कर निर्धारण से संबंधित आपत्तियों पर भी मौके पर सुनवाई की जाएगी।कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, ताकि प्राप्त शिकायतों का यथासंभव मौके पर ही निस्तारण किया जा सके और जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव न हो, उन्हें समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जा सके।नगर निगम की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे समाधान दिवस में समय से पहुंचकर अपनी शिकायत से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं, जिससे कार्रवाई शीघ्र और सुचारू रूप से पूरी की जा सके।इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस प्रशासन और जनता के बीच संवाद तथा विश्वास को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है। नगर निगम का निरंतर प्रयास है कि नागरिकों को एक ही मंच पर विभिन्न विभागों की संयुक्त उपस्थिति में उनकी समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जाए, जिससे शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो सके।

सच्ची भक्तिसमर्पण से - पंडित राजेश दीक्षित

(सुनील शर्मा)

लखीमपुर खीरी। भक्ति समर्पण का नाम है। सच्चा भक्त कभी छल कपट का व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं।जब तक हृदय में काम,क्रोध ा,लोभ, मोह, अहंकार का बसेरा है तब तक वे प्रभु मन मंदिर में नहीं आ सकते। प्रेम गली अति सांकरी तामें दो न समाय। समर्पण किया था हनुमान ने वे भगवान राम से अधिक पूज्य हो गये। समर्पण किया था अर्जुन ने बस फिर क्या था, स्वयं भगवान उनके सारथि बन गये। समर्पण किया था निर्जीव बांस की बांसुरी ने जो कृष्ण के ही अधरामृत का निरंतर पान करती रही। गोपियों को भी बांसुरी से ईर्ष्या होती थी। सच्चा समर्पण किया था मीरा ने भगवान उसके साथ नाचते गाते थे।उसका विष का प्याला भी अमृत हो गया,सर्प पिटारी फूलों की माला बन गई।जो भगवान को समर्पण कर कार्य करता है भगवान हर समय उसका सहयोग करते रहते हैं। उक्त विचार हैं श्री वेदमाता गायत्री प्रचार समिति के संस्थापक अध्यक्ष यज्ञाचार्य पं राजेश दीक्षित के जिन्होंने ग्राम कैमासुर सिद्ध बाबा स्थान पर पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ के छठे दिन यज्ञ कराते हुए कहे। महायज्ञ में कई लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। महायज्ञ में गीत संगीत प्रस्तुत किया विष्णु कुमार शर्मा व अमित जी ने।यज्ञ में सैकड़ों माताओं बहनों व परिजनों ने राष्ट्र कल्याण हेतु आहुतियां देकर अपने जीवन को ध न्य किया।

योगी सरकार का 'बिजली बचाओ अभियान' बेअसर! रजनी खंड पावर हाउस क्षेत्र में खुलेआम चल रहा अवैध कनेक्शन, अधिकारी फोन उठाने से कतरा रहे

लखनऊ। एक ओर योगी सरकार प्रदेशभर में बिजली बचाओ अभियान चलाकर बिजली चोरी पर सख्ती के निर्देश दे रही है और दोषियों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ के रजनी खंड पावर हाउस के अंतर्गत बिजली चोरी और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

सूत्रों से प्राप्त शिकायत के अनुसार रूची खंड–573 क्षेत्र में एक टेंपरेरी बिजली कनेक्शन ध ड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस कनेक्शन की सरकारी रसीद कटी है या नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं है। यह पूरा मामला अब जांच के दायरे में आता है। शिकायत की सत्यता जांचने के लिए समाचार कार्यालय द्वारा शारदा नगर क्षेत्र के जेई से उनके मोबाइल नंबर 8005481366 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद रजनी खंड पावर हाउस के लैंडलाइन नंबर 080–049–21256 पर भी जानकारी लेने की कोशिश की गई, मगर वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल खड़ा होता है कि

क्या बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं? क्या अवैध कनेक्शन विभागीय संरक्षण में चल रहा है?

और क्या सरकार के स्पष्ट निर्देश केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं? यदि समय रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो यह न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि योगी सरकार की सख्त छवि पर भी सवालिया निशान खड़ा करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

काव्य गोष्ठी के साथ हुआ स्मृति सम्मान के दूसरे संस्करण का आयोजन

लखीमपुर खीरी। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर गत दिवस गोला गोकर्णनाथ शहर के मोहल्ला पश्चिमी दीक्षिताना मे श्री छोटेलालदृसुखदेवी स्मृति सम्मान के दूसरे संस्करण का आयोजन काव्य गोष्ठी के साथ किया गया जिसका संचालन विश्व रिकार्ड धारी कवि एवं गद्यकार यतीश शुक्ला द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि गेंदन लाल कनौजिया द्वारा सरस्वती वंदना के साथ की गई। आगंतुक कवि श्रीपाल जी द्वारा महिलाओं को समर्पित कविता के साथ ही रमाकांत चौधरी द्वारा राजनीति को संबोधित कविता की गई इसी क्रम में रविसुत शुक्ल एवं सुधांशु त्रिवेदी द्वारा देश के ज्वलंत मुद्दों पर कविता की गई ,एस पी पाण्डेय द्वारा संस्कृत विधा के श्लोक पाठ उपरांत माता पिता को समर्पित रचना पढ़ी गई साथ ही राजेश मोहन द्वारा मां को समर्पित कविता के साथ ही चंद्रकांत द्वारा बशीर बद्र तथा संत कुमार बाजपेई को याद किया गया अनंग वर्मा द्वारा जहां है विराजमान बाबा... समाजसेवी नानक चन्द द्वारा राजनीति पर व्यंग्य तथा वरिष्ठ कवि श्रीकांत द्वारा कभी मेरे बच्चे तंबाकू न खाना... संदेश के साथ ही कवि वेद प्रकाश अग्निहोत्री द्वारा प्यारे बच्चों अमर गीत का पहले नाम बताना ... रचना पाठ किया गया। विशिष्ट अतिथि नानकचन्द वर्मा एवं मुख्य अतिथि सौरभ दीक्षित द्वारा सभी कवियों का कार्यक्रम उपरांत प्रतिभा अलंकरण करते हुए सभी को मोमेंटो प्रदान किए गए तत्पश्चात कार्यक्रम के आयोजक अनंग वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया द्वारा सभी को आभार प्रकट करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गईं।

कार चालकों को बड़ी राहतः 1 फरवरी 2026 से नए FASTag के लिए ज्ञल्ट प्रक्रिया समाप्त, सक्रियण होगा और आसान

लखनऊ। आम सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत देते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कारों (कारध्जीपध्वैन श्रेणी) के लिए जारी किए जाने वाले नए FASTag पर लागू नो योर व्हीकल (ज्ञल्ट) प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया है। यह नया प्रावधान 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। अब तक FASTag जारी होने के बाद ज्ञल्ट संबंधी औपचारिकताओं के कारण वाहन चालकों को बार–बार असुविध ा और देरी का सामना करना पड़ता था। NHAI के इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों को सक्रियण के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। NHAI ने स्पष्ट किया है कि कारों के लिए पहले से जारी मौजूदा थ्ंेज्ंह पर भी अब नियमित रूप से ज्ञल्ट अनिवार्य नहीं होगा। ज्ञल्ट केवल उन्हीं मामलों में आवश्यक होगी, जहां किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, जैसे ढीला FASTag, गलत तरीके से जारी किया जाना या दुरुपयोग से जुड़े मामले। यदि कोई शिकायत नहीं है, तो मौजूदा FASTag उपयोगकर्ताओं को किसी अतिरिक्त ज्ञल्ट प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सक्रियण से पहले सख्त सत्यापन व्यवस्था लागू FASTag प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए NHAI ने जारीकर्ता बैंकों के लिए पूर्व–सक्रियण सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया है। अब थ्ंेज्ंह का सक्रियण केवल VAHAN डेटाबेस से वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। इसके साथ ही सक्रियण के बाद किसी भी प्रकार के सत्यापन की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब वाहन का विवरण ट।भ्।छ पर उपलब्ध नहीं होगा, तब ही जारीकर्ता बैंक सक्रियण से पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) के आधार पर सत्यापन कर सकेंगे। इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित बैंक की होगी। ऑनलाइन माध्यम से बेचे जाने वाले थ्ंेज्ंह भी अब तभी सक्रिय किए जाएंगे, जब बैंकों द्वारा सभी आवश्यक सत्यापन पूरे कर लिए जाएंगे। NHAI का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य FASTag पारिस्थितिकी तंत्र को नागरिक–अनुकूल, तकनीक आधारित और शिकायत–मुक्त बनाना है। सक्रियण से पहले सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी जारीकर्ता बैंकों पर डालकर NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को अधि क सहज और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।

नववर्ष पर संवेदनशील प्रशासन का दोहरा संदेश, कलेक्ट्रेट में बांटी मिठास, अटल सभागार और वृद्धाश्रम में बंटी गर्माहट

डीएम दुर्गा शक्तिनागपाल की पहल से कर्मचारियों में उत्साह, जरूरतमंदों के चेहरे खिले

लखीमपुर खीरी, 01 जनवरी। नव वर्ष 2026 की पहली सुबह जनपद में एक साथ अनुशासन, संवेदना और सेवा की मिसाल बनकर सामने आई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जहां कलेक्ट्रेट में दफ्तर–दफ्तर और पटल–पटल पहुंचकर अधिकारियों व कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं, वहीं जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर प्रशासन के मानवीय चेहरे को भी मजबूती से उभारा। नववर्ष के पहले कार्यदिवस पर डीएम का आत्मीय अंदाज कलेक्ट्रेट में चर्चा का विषय रहा। उन्होंने अधिकारियों–कर्मचारियों से सीधे संवाद कर बीते वर्ष के कार्यों की सराहना की और सभी को मिठाई खिलाकर नए साल की मिठास बांटी। उनके इस व्यवहार से पूरे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और अर्चना ओझा ने भी मिठाई वितरण में सहभागिता की। डीएम ने स्पष्ट किया कि अनुशासन, समर्पण और टीम भावना ही सुशासन की असली पहचान है। नववर्ष पर प्रशासन की दूसरी सशक्त तस्वीर कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और डीएम की पहल पर आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में करीब 200 समाचार पत्र वितरकों, निराश्रित, असहाय गरीबों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर राहत और मुस्कान साफ नजर आई। सभी को लंच पैकेट भी दिए गए। कार्यक्रम का सफल संयोजन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि आमजन तक खबर पहुंचाने वाले समाचार पत्र वितरक समाज की आंख और कान हैं। ठंड, गर्मी और बारिश हर मौसम में बिना छुट्टी सुबह–सुबह अखबार पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। वितरक सच्चे अर्थों में कर्मयोगी और समाज के सजग प्रहरी हैं। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी गरीब ठंड से परेशान न रहे। इसी क्रम में प्रशासन निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों और समाचार पत्र वितरकों को सर्दी से राहत देने के लिए कंबल वितरित कर रहा है। उन्होंने स्वयं लाभार्थियों को कंबल ओढ़ाकर ठंड से बचाव की अपील की। वृद्धजनों का सहारा बनीं डीएम, आश्रम में बांटी गर्माहट

वृद्धाश्रम पहुंचकर लिया आशीर्वाद, कंबल पाकर खिल उठे बुजुर्गों के चेहरे

इसके बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल वृद्धाश्रम पहुंचीं। उन्होंने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह के साथ समाज कल्याण विभाग से वित्तपोषित 90 वृद्धजनों को कंबल और फल, मिष्ठान, समोसा आदि खाद्य सामग्री वितरित की। बुजुर्गों के चेहरे खुशी से खिल उठे। डीएम ने 44 पुरुष और 46 महिला वृद्धजनों का हालचाल जाना और कहा कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए सावधानी जरूरी है। डीएम ने आश्रम प्रबंधक और स्टाफ को निर्देश दिए कि वृद्धजनों को यह अहसास न हो कि वे अकेले हैं।

उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और संबंधित अधिकारियों व सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को कोई असुविधा न हो और शासन द्वारा अनुमन्य सभी सुविध ाएं समय से मुहैया कराई जाएं। इस दौरान एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह मौजूद रही।

सीओ ने चौकीदारों को वितरित किए कंबल

धौरहरा खीरी। ठिठुरती ठंड से बचाने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी शमशेर बहादुर सिंह व थानाध्यक्ष ईसानगर निर्मल तिवारी ने चौकीदारों के लिए दरियादिली दिखाते हुए दोनो अधिकारियों ने ईसानगर थाना क्षेत्र के 53 चौकीदारों को गरम कंबल वितरित किए ताकि रात्रि गस्त में चौकीदार ठंड से परेशान न हों। क्षेत्राधिकारी ने चौकीदारों को कंबल वितरण के दौरान निर्देशित किया कि गांव मे हर गलत गतिविधि ा पर नजर रखें। गांव कोई अपरिचित दिखें उससे परिचय जरूर पूंछे। कच्ची शराब, जुआ, चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चौकीदार की भूमिका सबसे अच्छी रहती है। प्रत्येक चौकीदार गस्त करे और सूचना समय से थाने को दे। कंबल पाकर चौकीदार के चेहरे खिले खिले नजर आये। साथ ही सीओ शमशेर बहादुर सिंह व थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी का आभार जताया ।

रेलकर्मियों और रंगकर्मियों ने सफदर हाशमी को किया नमन,श

लखनऊ। संस्कृतिकर्मी, लेखक एवं नाटककार सफदर हाशमी और रामबहादुर नेपाली की पुण्यतिथि पर सवारी माल डिब्बा कारखाना में अमुक आर्टिस्ट ग्रुप एवं उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की ओर से हुआ कार्यक्रम

लखनऊ,1 जनवरी। जानेमाने संस्कृतिकर्मी, लेखक एवं नाटककार सफदर हाशमी और रामबहादुर नेपाली की पुण्यतिथि पर शहर के रंगकर्मियों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम गुरुवार को आलमबाग स्थित सवारी माल डिब्बा कारखाना में अमुक आर्टिस्ट ग्रुप एवं उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की ओर से हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत सफदर हाशमी और रामबहादुर नेपाली के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री श्री अरविंद सिंह, शाखा अध्यक्ष दिनेश यादव, शाखा उपाध्यक्ष अभिनीत कुमार जैन, जूनियर इंजी. राम अवतार सिंह, वरिष्ठ खंड अभियंता जितेंद्र कुमार वर्मा, अमुक आर्टिस्ट ग्रुप के मुखिया संस्कृतिककर्मी अनिल मिश्र गुरू जी ने सफदर हाशमी और राम बहादुर नेपाली के चित्र पर श्रद्धासुमन आर्पित कर उन्हें नमन किया।

नाट्य प्रस्तुति से पहले कलाकारों ने जनगीतों की प्रभावी प्रस्तुति कर कर्मचारियों में जोश भर दिया। एक के बाद एक शानदार गीतों से पूरा देशभक्ति का वातावरण बना दिया। अनिल मिश्र गुरुजी के निर्देशन, परिकल्पना एवं लेखन में हम क्रांति करेंगे का प्रभावपूर्ण मंचन हुआ। जिसमें शशांक पांडेय, अनामिका सिंह, शोभित राजपूत, राहुल प्रताप सिंह एवं ज्योति ने भावपूर्ण अभिनय किया। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री श्री अरविंद सिंह ने कहा कि सफदर हाशमी और राम बहादुर नेपाली की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। उनके सामाजिक योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। रेलवे के कार्यरत सभी कर्मियों जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। रेलवे में उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन एक मात्र यूनियन ऐसी है, जो रेल कर्मियों की पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है। कर्मियों के हक का यह संघर्ष आगे जारी रहेगा।

अभिनीत कुमार जैन ने सफदर और रामबहादुर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि आज के समय में संस्कृतिकर्मी सफदर और राम बहादुर नेपाली जैसी विभूतियों की जरूरत है। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजवीर रतन, नाट्य निर्देशक धरमश्री सिंह, अनूप मिश्र, अध्ययन, आद्या, अभिनेता सोनल ठाकुर, शाश्वत शुक्ल, जादूगर सुरेश, चित्रकार विनोद विश्वकर्मा, समेत अनेक नाट्यकर्मी व रेलकर्मी मौजूद रहे।

केजीएन लाइव न्यूज चौनल के कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन

लखीमपुर खीरी। नव वर्ष 2026 के पावन अवसर पर जनपद में केजीएन लाइव न्यूज चौनल सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क के कार्यालय का भव्य उद्घाटन मेला मैदान परिसर में उत्साह और गरिमामय वातावरण के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले के पत्रकारिता जगत से जुड़े अनेक वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया कर्मी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने न केवल नए साल की खुशियों को साझा किया, बल्कि डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में केजीएन लाइव न्यूज चौनल की मजबूत शुरुआत को भी दर्शाया। कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार अमीर राजा पम्मी द्वारा फीता काटकर किया गया। फीता काटते ही उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ नव स्थापित कार्यालय का स्वागत किया। इस मौके पर अमीर राजा पम्मी ने केजीएन लाइव न्यूज चौनल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म समाज की आवाज को मजबूती से उठाने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केजीएन लाइव न्यूज चौनल निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों को अपनाते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सामने लाएगा। उद्घाटन समारोह में केजीएन लाइव न्यूज चौनल सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क के संपादक अमित मौर्य, सह–संपादक मुजीबुर रहमान खान, मंडल प्रभारी अंशुमान सिंह, जिला प्रभारी रमेश मौर्य, तहसील प्रभारी गोपाल कृष्ण, संवाददाता पवन कुमार सहित जनपद के अनेक वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया प्रतिनिधि ा मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने नए कार्यालय का अवलोकन किया और चौनल की टीम को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता, सोशल मीडिया की भूमिका और स्थानीय मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी हुई।

इसी अवसर पर केजीएन लाइव न्यूज चौनल के संपादक अमित मौर्य का जन्मदिन भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यालय परिसर में केक काटकर जन्मदिन की खुशियां साझा की गईं। उपस्थित पत्रकारों और अतिथियों ने अमित मौर्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि अमित मौर्य के नेतृत्व में केजीएन लाइव न्यूज चौनल ने कम समय में ही अपनी अलग पहचान बनाई है और लगातार जनपद की समस्याओं, सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहा है। अपने संबोधन में संपादक अमित मौर्य ने सभी अतिथियों, वरिष्ठ पत्रकारों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केजीएन लाइव न्यूज चौनल का उद्देश्य सच्ची, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता की आवाज बनना है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चौनल भविष्य में भी जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक की खबरों को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करता रहेगा। भव्य उद्घाटन समारोह और जन्मदिन उत्सव के साथ केजीएन लाइव न्यूज चौनल के कार्यालय की शुरुआत लखीमपुर खीरी जनपद के मीडिया जगत के लिए एक महत्वपूर्ण और यादगार क्षण बन गई, जो आने वाले समय में डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने का कार्य करेगी।

आपदा प्रबंधन में योगी सरकार की संवेदनशील पहल

प्रयागराज(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में आपदा से प्रभावित आश्रितों का दर्द साझा करने में प्रदेश की योगी सरकार ने संवेदनशील पहल की है। सरकार ने प्रदेश में बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली, लू और शीत लहर जैसी आपदाओं से निपटने के लिए तकनीकी की मदद ली है जिससे अब राहत वितरण अब त्वरित और पारदर्शी माध्यम से आश्रितों तक पहुंच रहा है ।आपदा प्रबंधन में तकनीकी का उपयोग प्रभावी साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की संवेदनशील और तकनीक आधारित व्यवस्था के चलते अब आपदा पीड़ित (मृतक आश्रित परिवार) परिवारों को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है । प्राकृतिक, स्थानीय अथवा गैर–प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के निकटतम आश्रितों को अब महज 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिल रही है। प्रयागराज मंडल में अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के बीच विभिन्न कारणों से हुई 523 जन हानियों के मामलों में सरकार द्वारा ६20.68 करोड़ की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।

प्रयागराज की एडीएम एफ आर विनीता सिंह का कहना है कि जिले में इस अवधि में 170 जनहानि हुई जिसमें आश्रित परिवारों को ६6.80 करोड़ मुआवजे की धनराशि 24 घंटे के अंदर वितरित की गई। इसमें भी बाढ़ में डूबने की वजह से सर्वाधिक 100 की जनहानि दर्ज की गई है।इस अवधि में फतेहपुर जिले में 140 की जनहानि हुई जिसमें 5. 60 करोड़ की मुआवजा राशि उन्हें 24 घंटे के अंदर वितरित की गई है। मंडल में प्रतापगढ़ जिले में 113 की जनहानि हुई जिसमें 4.50 करोड़ की मुआवजा राशि आश्रित परिवारों को त्वरित गति से वितरित की गई है। कौशाम्बी जिले में इस दौरान 94 जन हानियां दर्ज हुई हैं जिसमें 3.76 करोड़ की मुआवजा राशि आश्रित परिवारों को 24 घंटे के अंदर वितरित की गई है। यूपी में आपदा से मृत्यु के मामलों में सहायता वितरण की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन है जिसमें लेखपाल द्वारा आवेदन और दस्तावेज अपलोड, फिर कानूनगो, तहसीलदार और अंत में एडीएम स्तर पर सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में राशि भेजी जाती है। लेकिन अब योगी सरकार इसके लिए राहत पोर्टल और आपदा प्रहरी ऐप को प्रभावी रूप से लागू किया । इन माध्यमों से राहत वितरण अब त्वरित, ट्रैकिंग योग्य और जवाबदेह बन गया है। आंकड़ों के अनुसार, बीते तीन महीनों में राज्य स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक मामलों में यह सहायता 24 से 48 घंटे के भीतर दी गई है।

नियमानुसार प्रत्येक मृतक के आश्रित को ६4 लाख की सहायता 24 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

चेयरमैन लखीमपुर खीरी मनोनीत

लखीमपुर खीरी। सामाजिक कार्यकर्ता जसपाल सिंह पाली की शोषित वंचित एवं किसानो की प्रति मेहनत व लगन को देखते हुएअन्तराष्ट्रीय मनावाधिकार सुरक्षा समिति ने जनपद लखीमपुर खीरी का चेयरमैन मनोनीत किया है। श्री पाली INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION COUNCIL संगठन का विस्तार करेगें तथा सामजिक, शोषित, वंचित असहाय किसानों की मदद करेगें एवं हक दिलवायेंगें तथा सरकारी विभागो से विभिन्न योजनाओ का लाभ वंचित व्यक्तियो को दिलवायेंगें। यह नियुक्ति कौंसिल के राज्य (यूपी) चेयरमैन टीएन मिश्र ने की है।

ठंड से बचाने के लिए जगह-जगह जल रहे अलाव

जनता बोली कि देर रात जलते हैं अलाव

(मनोज मिश्र)

धौरहरा खीरी। गत लगभग तीन सप्ताह से चल रही भीषण शीत लहर में आम आदमी को ठंड से बचाने के लिए शासन द्वारा इसके लिए गर्म कंबलों से लेकर अलाव जलाने आदि के लिए ध नराशि आवंटित कर भेजी जाती है। इसी कड़ी में नगर पंचायत धौरहरा प्रशासन द्वारा वर्तमान सत्र में लगभग दो सौ जगहों पर गीली लकड़ी से अलाव जलवाकर आम आदमी के लिए गर्मी पैदा कर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के निर्देश पर आम आदमी व गौवंशीय पशुओं को तराई क्षेत्र पड़ रही भयानक ठंड से बचाने के लिए ग्राम पंचायत,नगर पंचायत व ग्राम पंचायतो के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया था। इसी क्रम में नगर पंचायत प्रशासन धौरहरा ने सीमा विस्तार सहित क्षेत्र में वर्तमान ठंड के सीजन में लगभग 200 जगहों पर गीली लकड़ी के सहारे अलाव जलवाकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाहन करते दिखाई पड़ रहे। ग्रामीणों के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी देर रात से अलाव जलाने का काम करते हैं।

अधिशासी अधिकारी धौरहरा गौरव सिंह ने बताया कि पूरे नगर क्षेत्र में लगभग दो सौ जगहों पर अलाव जलते हैं।एक अलाव में कितनी लागत लगती है से संबंधित सवाल करने पर ईओ ने बताया कि फाइल देखकर बता देंगे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.
9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।